सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-326
09/08/2017

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 09 अगस्त 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

बैठक के उपरांत विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा ने बताया कि राज्य में सभी ग्रामीण पथों की मानचित्र लंबाई 129473 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 69000 किलोमीटर की लंबाई में पथों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विभाग के समक्ष अगले तीन वर्षों में लगभग 60900 किलोमीटर की लंबाई में पथों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिये वास्तविक कार्य योजना बनायी गयी है और तदनुसार आवश्यक राशि का भी आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल बसावट की संख्या 129209 है, जहॉ से लगभग 68200 बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है और लगभग 61000 बसावटों को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सम्पर्कता प्रदान कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग को मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में निदेश दिया गया था कि सड़कों की लंबाई तथा आवश्यक राशि का सटीक आकलन करे। इस संबंध में आज ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सत्यापन के प्रस्ताव के उपरांत पथों की निर्मित एवं प्रस्तावित लंबाई तथा बसावटों की जनसंख्या की डिबार विवरणी प्रदान की गयी है।

विकास आयुक्त ने बताया कि सात निश्चय के तहत ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना में 4643 उक्त टोले को सम्पर्कता प्रदान की जानी है। ये उक्त टोलें आम तौर पर समाज के पिछड़े एवं कमजोर तबके के टोले हैं। अभी तक लगभग एक तिहाई ऐसे टोलों की सम्पर्कता देने की योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और इसी वर्ष शेष टोलों की सड़कों की योजनाओं की स्वीकृति दे दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य ने सबसे अधिक लंबाई में पथ का निर्माण करने तथा सबसे अधिक संख्या में बसावटों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

विकास आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नये अभिनव तकनीकों का प्रयोग करने तथा मुख्य रूप से वेस्ट प्लास्टिक के प्रयोग से सड़क के निर्माण करने के संबंध में पृच्छा की। विभाग द्वारा बताया गया कि इस वर्ष लगभग 374 पथों में 657 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पथों का निर्माण करने के क्रम में वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग किया जायेगा और इससे कचरा प्रबंधन में सहुलियत होने के साथ–साथ विटुमिन की मात्रा 8 प्रतिशत तक कम होगी और इस कार्य में लगे लोगों को एक नियमित रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा राज्य के पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण कर पर्यटन सम्पर्क योजना बनायी जा रही है।

विकास आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सुक्ष्मतापूर्वक विभाग की प्रस्तुती की समीक्षा की। योजनाओं को चरणबद्ध ढ़ंग से क्रियान्वित करने तथा अगले तीन वर्षों में प्रत्येक योग्य बसावटों को जोड़ने के अभियान को तेज करने का निदेश दिया।

समीक्षा के दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित ग्रामीण कार्य विभाग के अन्य वरीय अधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।

******